International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 7.150, Volume 06, No. 04(I), October - December, 2024, pp. 98-102

भारतीय राजनीति में अपराधीकरणः कारण और प्रभाव

डॉ. सरोज सीरवी*

सार

वर्तमान में लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय शासन पद्धति के रूप में स्वीकार्य है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जिसमें लोकतंत्र में जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया जाता है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है जो निर्वाचन के समय सभी दल अपने प्रतिनिधियों को चुनावी मैदान में उतारती है। संसदीय शासन में बहुमत दल को सरकार बनाने का मौका मिलता है। निर्वाचन के समय कोई भी पार्टी बहुमत से पीछे ना रह जाए भरसक प्रयास करती है उसके लिए नैतिकता को एक तरफ रखकर किसी भी तरीकों को अपना सकती है। निर्वाचन प्रणाली में अनेक बुराइयों एवं चुनौतियां के कारण दूषित हो गई है, ऐसी ही चुनौतियों में से एक है– राजनीति का अपराधीकरण। प्रस्तुत आलेख भारतीय राजनीति का अपराधीकरण निरंतर बढ़ रहा है जिसके कारण संसद, विधानसभा में अपराधी सांसदों एवं विधायकों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। भ्रष्टाचार एवं अपराधीकरण की समस्या पर प्रकाश डालना एवं संकल्प शक्ति निश्चित करने हेतु संक्षिप्त विवरण इस आलेख में समाहित है।

शब्दकोशः *अपराधियों का राजनीतिकरण के कारणों, सुझावों, पार्टियों में दागी सांसद।*

प्रस्तावना

प्रत्येक राष्ट्र अपनी सभ्यता, संस्कृति, आदर्श, मूल्य तथा सामाजिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के आधार पर न केवल कार्य करता है अपितु गर्व भी करता है। भारत एक प्राचीन राष्ट्र है जिसकी सभ्यता, संस्कृति, आदर्श गौरवशाली रहे हैं। दुर्भाग्यवश स्वतंत्रता के पश्चात इन मूल्यों एवं आदर्श में गिरावट देखने को मिलती है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रक्रिया तभी सार्थक मानी जाती है, जब इसका संचालन पारदर्शिता, निष्पक्षता और नैतिकता के साथ हो। आज भारत संकट और समस्या के दौर से गुजर रहा है। भारतवर्ष अपने 5000 वर्ष के इतिहास में कभी अधोगति की ऐसी स्थिति में नहीं पहुंचा, जिस स्थिति में आज पहुंच गया है। आज महान राष्ट्र नैतिक पतन से ग्रस्त है जिसके कारण अनेक ज्वलंत समस्याओं व प्रश्नों से घिरा हुआ है जैसे– अपराधीकरण, घपलों, घोटालों और भ्रष्टाचार में डूबी राजनीति रीढ़विहीन राजनीति, गठजोड़, दलबल की राजनीति, चुनावों में बढ़ती हिंसा, भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता, जातिवाद की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, राजनीतिक नेतृत्व का अभाव, अवसरवादी राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति, संसद का गिरता स्तर, लोकतंत्र, आजादी और संवैधानिक प्रावधानों का मजाक, सत्ता की शतरंज आदि। जिनमें से सबसे गंभीर समस्या है राजनीति का अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह दोनों स्थितियों वर्तमान शासक वर्ग की राजनीतिक संस्कृति की एक विशेषता बन गई है। राजनीति के अपराधीकरण का आशय है कि ''अपराधियों का राजनीतिक दलों तथा संसद सहित सभी विधायी संस्थानों में सीधे प्रवेश।

* सहायक आचार्य (गेस्ट फेकल्टी), राजनीति विज्ञान विभाग, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान।

राजनीतिक प्रक्रिया और कामकाज को प्रभावित करने के लिए आपराधिक ढंग और तौर–तरीकों का प्रयोग भी राजनीति के अपराधीकरण में ही आते हैं।'' राजनीति में चुनाव जीतने, आगे बढ़ाने एवं सत्ता प्राप्त करने के लिए अपराध और अपराधियों का प्रयोग ही राजनीति को दूषित बना रहे हैं। अपराध के राजनीतिकरण में दलीय कोष एकत्रि करने, चुनाव का प्रबंध करने तथा बैठकें और सम्मेलन आयोजित, समाज विरोधी तत्वों को राजनीतिक कार्यकर्ता बनाना और उनको सम्मिलित करना, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक माना जाने लगा है। जब राजनीतिक महत्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपराध का सहारा लेना राजनीतिक अंग बन गया है तो ऐसी स्थिति में अपराधी के सत्ता तक पहुंचने की आकांक्षाएं प्रबल हो जाती है एवं राजनीति में प्रवेश कर अपना उद्देश्य पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टियां व अपराधी दोनों की इच्छा पूरी हो जाती है। किसी न किसी तरह सत्ता तक पहुंचने की आकांक्षा की अपराध प्रधान साधनों– भ्रष्टाचार, लूट, हत्याओं का सहारा लेकर धूर्त, दुष्ट और बदमाश राजनीति में पहुंच जाते हैं एवं सांसद, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अपराधी राजनीतिज्ञों का बाना धारण कर लेते हैं। जो पहले अपराधी थे वह राजनेता, सांसद, मंत्री, विधायक बनकर प्रशासन को प्रभावित करने लगते हैं।

वर्तमान में भारतीय राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था को खोखला करने में सबसे अधिक भूमिका निभा रहे हैं– भ्रष्टाचार (करप्शन), जातिवाद (कास्टिज्म), और अपराधीकरण (क्रिमिनलाइजेशन)। राजनीतिक अपराधीकरण देश की सभी समस्याओं की जड़ है। इसके सहारे सभी समस्याएं फलती फूलती हैं। लोकतंत्र प्रक्रिया में अपराधी आसानी से अपना उद्देश्य पूरा कर लेते हैं जिसके और भी कई कारण है जो राजनीति के अपराधीकरण को बढ़ावा देते हैं–

नैतिक मूल्यों का पतन के कारण भारतीय राजनीति में जो प्रवृत्ति उभर रही है वे है– राजनीति का व्यवसायीकरण, भ्रष्टाचार, अवसरवादी गठबंधनों की प्रवृत्ति, पद व सत्ता को लोलुपता, क्षेत्रीयता, जाति, धर्म व संप्रदाय की राजनीति, व्यक्ति–पूजा, सांसद व जन प्रतिनिधियों की गुणवत्ता में निरंतर ह्रास आदि, राजनीति अपराधीकरण को बढ़ावा देते रहते हैं।

गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, युवा वर्ग, विशेषतया शिक्षित बेरोजगारों को राजनीति के अपराधीकरण की ओर धकेला है।

संपन्न वर्ग के युवाओं में असीमित लालसाएं और नैतिक पतन भी राजनीति अपराधीकरण की ओर ले जाता है।

सत्ता प्राप्त राजनीतिक दलों का एकमात्र लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना है इसके लिए वे येन–केन–प्रकारेण किसी भी साधनों एवं नीतियों को अपना लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लेते हैं।

प्रशासन और पुलिस में राजनीतिक हस्तक्षेप कर उन्हें डराना–धमकाना एवं दबाव बनाते हैं जिससे प्रशासन के मनोबल में गिरावट आ जाती है तो छल, कपट, धूर्तता तथा इन सब के अतिरिक्त साधनों के धनी ये अपराधी और आपराधिक रिकार्ड वाले राजनीतिज्ञ समूची व्यवस्था पर हावी हो जाते हैं।

अनवरत चुनाव और अहर्निश सत्ता राजनीति का दुश्चक्र लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता को आघात पहुंचाते हैं तथा अपराधियों को प्रोत्साहित करते हैं। अपराधियों का राजनीति में प्रवेश चुनाव से प्रारंभ होता है। प्रारंभ में वे फर्जी मतदान, मतदान केद्रो पर कब्जा, धमकी, मारपीट, गुंडागर्दी आदि के आधार पर उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को मदद देकर उनके निकट आते हैं। आए दिन चुनावों की वजह से बड़ी संख्या में अपराधियों को राजनीति में प्रवेश दिया जाता है। इसके साथ ही संसदीय व्यवस्था के कारण प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री का कार्यकाल बहुमत पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को सदैव ही अपने पक्ष और विपक्ष के विधायकों की गिनती करनी होती है। सत्ता राजनीति, दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनावी राजनीति और स्वयं राजनीतिज्ञ राजनीति के अपराधीकरण के लिए प्रमुख रूप से दोषी हैं। ''अपराधी गिरोह राजनीतिक संरक्षण में फलफूल रहे हैं। राजनीतिज्ञों और अपराधियों का गठबंधन एक समानांतर सरकार चला रहा है, जिसे राज्य को अप्रासंगिक कर दिया है।

अपराधी राजनीतिज्ञों की जनता में स्वीकार्यता भी एक बहुत बड़ा कारण है। कई बार जनता क्षेत्रीय समस्याओं एवं जाति प्रमुख की भूमिका निभाती है जिससे अपराधी को चुनाव में लाभ मिल जाता है।

शासन की क्षमता, गुणवत्ता और प्रतिष्ठा में सुधार के राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति का सर्वत्र अभाव है जिससे अपराधी अपने स्वार्थ सिद्धि में सफल हो जाते हैं एवं उनका हौसला बढ़ जाता है।

समाज में बढ़ते हुए अपराधों और अपराधियों के सामाजिक व्यवस्था तथा राजनीति में प्रतिष्ठित हो पाने का एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण देश की समस्त आपराधिक न्याय व्यवस्था का अत्यधिक दोषपूर्ण होना है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में मामलों का लंबा खींचना और धीमी प्रक्रिया अपराधियों को राजनीति में आने का अवसर देती है। दोषी साबित न होने तक, कानून ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकता, जिसका लाभ अपराधी तत्व उठाते हैं।

आज राजनीति का अपराधीकरण एवं भ्रष्टाचार एक सिक्के के दो पहलू बन चुके हैं। कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसमें अपराधी छवि वाले नेता ना हों। ऐसे अनेक नेता है जिन पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, हत्याएं, दंगों जैसे आपराधिक मामले, धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप, फिरौती, आय से अधिक संपत्ति के आरोप लगे हैं फिर भी वह चुनाव जीतकर अपराधी से राजनीतिज्ञ बन जाते हैं एवं समाज में निःसंकोच एवं शान से रहते हैं।

राजनीतिक अपराधियों द्वारा अनेक राजनीतिक घोटालों का इतिहास भरा पड़ा है, जैसे–

- प्रतिभूति घोटाला (हर्षद मेहता) 1992
- जीप–राइफल खरीद घोटाला, 1948
- हीरा की खान घोटाला, 1956
- भारतीय जीवन बीमा निगम घोटाला, 1957
- कैरी घोटाला, 1964
- नागर वाला कांड, 1971
- मारुति उद्योग कांड, 1975
- इंडियन ऑयल कांड, 1980
- सीमेंट घोटाला
- बोफोर्स कांड, 1987
- पनडुब्बी घोटाला, 1987
- कोयला घोटाला, 1989
- चारा मशीन घोटाला, 1989
- एयरबस घोटाला
- चीनी खरीद घोटाला, 1993
- झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, 1993
- बिहार चारा घोटाला, 1994
- शेयर घोटाला, 2001
- जी स्पेक्ट्रम घोटाला
- राष्ट्रमंडल खेल

- संसद में रिश्वत कांड
- यूरिया
- टेलीफोन
- शराब नीति घोटाला, आदि अनेक खुले रूप में भ्रष्टाचार किया जाता है।

राजनीतिक अपराधीकरण का वर्णन एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर एवं इंडियन वॉच के अध्ययन के अनुसार 2004 के 14वी लोकसभा आम चुनाव में 24 प्रतिशत, 2009 के 15वीं लोकसभा के चुनाव में 30 प्रतिशत तथा 16वीं लोकसभा में 34 प्रतिशत सांसद आपराधिक पृष्ठभूमि के थे।

एडीआर द्वारा 17वीं लोकसभा (2019) के उम्मीदवारों द्वारा दिए गए चुनावी हलफनामों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि चयनित सांसदों में से 29 प्रतिशत सांसद ऐसे हैं जिनके विरोध गंभीर मामले दर्ज हैं। संसद, विधानसभा, पंचायत हर स्तर के चुनावों में परंपरागत बाहुबलियों, पेशे से अपराधियों, भूमाफियाओं, तस्करों एवं नक्सलवादियों का दबाव बढ़ता जा रहा है जिससे देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं न्याय व्यवस्था, प्रशासन के सामने एक चुनौती बनकर देश को कमजोर कर रहा है। राजनीति अपराधीकरण लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करती है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। विकास कार्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एवं सामाजिक अस्थिरता बढ़ती है। प्रशासन एवं न्याय व्यवस्था कमजोर पड़ती है। राजनीतिक अपराधीकरण भ्रष्टाचार, घपलों, घोटालों में डूबी राजनीति, दलबल की राजनीति तथा राजनीतिक मुर्गबाजी, चुनावों में बढ़ती हिंसा, अपव्यय, सत्ता की शतरंज, प्रतिशोध की राजनीति, लक्ष्य विहीन एवं अवसरवादी राजनीति, सांप्रदायिकता एवं जातिवाद की राजनीति, काला धन, के साए में पली राजनीति, सिद्धांतहीन राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति का अभाव, राजनीतिक मूल्यों की त्रासदी, संसद का गिरता स्तर, लोकतंत्र, आजादी और संवैधानिक प्रावधानों का मजाक, हत्याएं, आंतकी गतिविधि को बढ़ावा मिला है जो चिंतनीय विषय है। इतना नैतिक पतन हुआ है कि लगता है यदि भगवान भी जमीन पर आ जाएं तो वह देश को नहीं बचा सकते। फिर भी कुछ सुधार के सुझाव देकर आशावान बन सकते हैं। राजनीति अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए कुछ प्रमुख सुझाव–

अपराधिक गतिविधियों में संलग्न व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर कानूनी रोक की व्यवस्था होनी चाहिए। राजनीतिक दलों में चेतना जागृत किया जानी चाहिए ताकि वे अपराधियों को अपने साथ न जोड़े तथा उन्हें टिकट न दें।

आपराधिक कानूनी व्यवस्था और न्याय व्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण सुधारो की आवश्यकता है। न्याय शीघ्र एवं सर्वशुलभ न्याय होना चाहिए जिससे अपराधों को नियंत्रित किया जा सके।

शासन की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार हो ताकि शासन अपराधियों एवं आतंकवादियों के सामने घुटने नहीं टेके। कड़े फैसले लें ताकि अपराधियों के हौसले पस्त हो।

राजनीतिक दलों और राजनीतिक गतिविधियों में सुधार करें। किसी भी जाति–धर्म का अपराधी हो उसे राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं देनी चाहिए। अपराधियों को राजनीतिक पार्टी के किसी सभा, सम्मेलन में मंच पर स्थान नहीं देना चाहिए।

चुनाव व्यवस्था में सुधार करें और चुनावी राजनीति को व्यवस्थित करना चाहिए। चुनाव व्यवस्था को फर्जी मतदान और बाहुबल, धनबल की शक्ति से मुक्त करना होगा।

प्रेस और मीडिया अपनी भूमिका के प्रति बहुत अधिक सचेत हो और सतर्कता बरतें।

अपराध प्रवृतियों में संलग्न राजनीतिज्ञों के कारनामों को समाज के सामने उजागर कर लोगों को जागृत करें ताकि अपराधी प्रवृत्ति वाले राजनीति में ना आ सके। प्रेस व मीडिया अपराधियों को राजनीति से बाहर खदेड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

सामान्य अभिजन और मतदाताओं में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता करें, शिक्षित करें ताकि वह अपने मताधिकार का प्रयोग सोच–समझकर कर सकें।

भारतीय राजनीति में चैतन्य नागरिकता, राजनीतिक सुचिता, सिद्धांतयुक्त राजनीति, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, चुनाव कानून और प्रक्रिया में सुधार, सांप्रदायिक राजनीति पर अंकुश, प्रभावी कानून व्यवस्था, राजनीतिज्ञों के लिए आचार संहिता, अच्छे व्यक्ति राजनीति से जुड़ें। हमारी संस्कृति की जड़ें मजबूत हो, लोगों में लोकतांत्रिक भावना हो, नागरिकों में व्यक्ति हित नहीं, राष्ट्रीय हित की भावना हो तो काफी हद तक आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पा सकते हैं।

उपंसहार

भारतीय राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के प्रति समाज एवं सरकार दोनों ही चिंतित हैं। आज समय आ गया जब देश समस्त अच्छे तत्व चाहे राजनीति, सरकार, प्रशासन, व्यापार, शिक्षा, प्रेस और मीडिया जहां भी हो, एक–एक नैतिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की मांग करें। यदि हम इस समय अपराधीकरण को समाप्त करने में सफल नहीं होते हैं तो यह कैंसर रूपी बीमारी हमारा सर्वनाश कर देगी। अतः समय की मांग है कि राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक नेतृत्व, जनता, राजनीतिक दल सभी अपने–अपने तरीके से संकल्प शक्ति अपनायें तो इस दिशा में सफलता मिल सकती है। चुनाव में दंगल एवं बाहुबली के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाए। राजनीति में अपराधीकरण को नियंत्रित करने के लिए संस्थागत एवं गैर संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डॉ. पुखराज जैन, डॉ. बी.एल.फड़िया– 'भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स : आगरा
2. डॉ. रूपा मंगलानी– भारतीय शासन एवं राजनीति, अध्याय : भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की समसामयिक प्रवृतियां, राजस्थानी हिन्दी ग्रंथ अकादमी
3. डॉ. आर.एन.त्रिवेदी, डॉ. एम.पी.राय– भारतीय सरकार एवं राजनीति, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर
4. डॉ. संगतसिंह– 'भारतीय राजनीति में नैतिक संकट' अध्याय–22, भारतीय राजनीति में नैतिक अवमूल्यनः प्रवृतियां एवं परिदृश्य
5. आढ़ा, आर.एस.– भारत में निर्वाचन व्यवस्था : चुनौतियां एवं संभावनायें, एबीड पब्लिशर्स, जयपुर
6. सिंह, निर्मल कुमार– अपराध और भ्रष्टाचार की राजनीति, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली
7. गोयल, नरेश– भारतीय लोकतंत्र : राजनीति का अपराधीकरण व भ्रष्टाचार, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर
8. L.S. Rathore, "Political Cutlure of India's Rulling Class".

❖◆❖